भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1616
सोमवार, 3 अगस्त, 2026 (12 श्रावण 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

दूरस्थ जनजातीय और आकांक्षी जिलों में उड़ान योजना का विस्तार

1616. श्री प्रदीप कुमार वर्माः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के अंतर्गत देश के दूरस्थ, जनजातीय एवं आकांक्षी जिलों में हवाई संपर्क का विस्तार करने के लिए कोई विशेष रणनीति अपनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना के प्रारंभ से अब तक देश में कितने हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरोड्रोमों को परिचालन में लाया गया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के आगामी चरण के अंतर्गत पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड राज्य में हवाई संपर्क का विस्तार करने तथा नए हवाई मार्ग प्रारंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): एयरलाइनों को देश में असेवित/अल्पसेवित हवाईपट्टियों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले माँग आधारित बोली प्रक्रिया तंत्र के माध्यम से देश के दूरस्थ और असेवित क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। दिनांक 20.07.2026 तक, 'उड़ान' योजना के तहत देशभर में 17 हेलीपोर्टों और 02 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 95 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले कुल 679 आरसीएस मार्गों को प्रचालनरत किया गया है।

'उड़ान' योजना का अगला चरण झारखंड सहित देशभर के टियर 2 और टियर 3 शहरों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 04.07.2026 को शुरू किया गया है, जिसमें अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लक्षित किया गया है। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें पर्वतीय, पूर्वोत्तर और आकांक्षी (एचआईएनईआर) राज्यों/जिलों में एयरोड्रोम विकास के लिए 12,159 करोड़ रुपये और 200 हेलीपोर्टों के विकास के लिए 3,661 करोड़ रुपये शामिल हैं।

*****